an>

Title: Need to regularise the services of Para-teachers in Jharkhand and also enhance their honorarum including BRP and CRP teachers in the State.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) ः देश में कुल 15 लाख 22 हजार 346 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें झारखंड की संख्या 48,528 हैं। समूचे देश के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। 52 प्रतिशत पाँचवी कक्षा के छात्र सही से दूसरी कक्षा की हिन्दी की किताब तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। 31 मार्च, 2016 को देश में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों 51,81,791 में से (17.51 प्रतिशत) 9,07,585 पद रिक्त हैं। वहीं झारखण्ड में स्वीकृत 1,92,200 पदों में (38.39 प्रतिशत) 73,793 पद रिक्त हैं। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इकलौते शिक्षक वाले स्कूल न हों। वहीं माध्यमिक स्तर पर कुल स्वीकृत शिक्षकों के 6,44,826 में से (15.91 प्रतिशत) 102575 पद देश के स्कूलों में रिक्त हैं। झारखंड में माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत 22604 पदों में से (71.73 प्रतिशत) 16213 पद रिक्त हैं। देश में हजारों विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कोई शिक्षक नहीं है यानि बिना शिक्षकों के विद्यालय जिसका सरकार ने कभी मूल्यांकन भी नहीं किया है। एक शिक्षक के सहारे चल रहे सरकारी विद्यालयों की संख्या भी एक लाख से अधिक है। झारखंड के 7391 विद्यालयों को केवल एक शिक्षक चला रहे हैं।

स्कूलों के अध्यापकों को पढ़ाने के अलावा ढेर सारे दूसरे काम करने पड़ते हैं। अध्यापकों को चुनाव के समय पढ़ाने-लिखाने का काम छोड़कर चुनावी ड्यूटी निभानी पड़ती है। ग्रामीण स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों को तो जनगणना सहित कई तरह के सर्वे आदि में भी शामिल किया जाता है, इसके अलावा उन्हें पंचायत के भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आजादी के बाद कुछ समय तक ऐसा करना शायद जरूरी था, क्योंकि उस समय जिस तादाद में पढ़े-लिखे लोगों की जरूरत थी, उतने उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अब यह मजबूरी नहीं है, इस परम्परा को समाप्त किया जाना चाहिए।

मेरे द्वारा लोक सभा के मानसून सत्र में दिनांक 20 जुलाई, 2016 को झारखंड राज्य में शिक्षकों एवं स्कूलों की कमी तथा पारा शिक्षकों की मांगों का विषय शून्यकाल में उठाया था। झारखंड राज्य में पारा शिक्षक 14-15 वर्षों से काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य में लगभग 72000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। झारखंड में पारा शिक्षकों को 10,000 रूपये प्रतिमाह से भी कम वेतन मिलता है। झारखंड के पारा शिक्षकों द्वारा कई महीनों से मानदेय बढ़ाने, नियमित वेतन वृद्धि, समय पर भुगतान करने और स्थायी नियुक्तियों में समायोजन की मांगों को लेकर भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल होती रहती है, जिससे राज्य में बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। समय पर कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। केंद्र सरकार प्रारंभिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) और माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) के जरिए समुचित छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती हैं। इसी राशि से झारखंड में पारा शिक्षकों को वेतन दिया जाता है। केंद्र सरकार की योजना होने के कारण राज्य सरकार द्वारा पारा शिक्षकों के मानदेय एवं अन्य मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता है।

मेरी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग है कि पारा शिक्षकों सहित बी.आर.पी.-सी.आर.पी. शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण सम्मानजनक और शिक्षक पद की गरिमा के अनुरूप हो। साथ ही समय पर भुगतान हो। झारखण्ड में लगभग 72000 पारा शिक्षक हैं, वहीं शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 90000 से अधिक है। इसलिए स्थायी शिक्षकों की भर्ती नियमों में छूट देकर या सरल कर सभी योग्य पात्रता वाले प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का समायोजन किया जाए, जिससे शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जा सके और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। शिक्षा में गुणवत्ता की कमी को दूर किया जा सके। झारखंड के दयनीय शिक्षा परिदृश्य में अविलंब सुधार हेतु केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय शीघ्रातिशीघ्र पहल करे।